JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"चन्दौली जनपद के असंगठित क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक क्रियाओं का लघु उद्योग के विकास में भूमिका: एक जनपद एक उत्पाद योजना के विशेष सन्दर्भ मे"

अरुण यादव
(शोध छात्र)
अर्थशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश,भारत

सारांश (Abstract):-

वर्तमान समय में लघु उद्योग विशेष रूप से विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में जोड़े गए सकल औद्योगिक मूल्य की लगभग 40% योगदान करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अर्थात (MSME) चंदौली जनपद की तो लघु उद्योग लगभग 60 प्रतिशत योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में करता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य चंदौली जनपद के लघु उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए 'एक ज़िला एक उत्पाद' की रोजगार सृजनात्मक एवं ग्रामीण आर्थिक विकास गति को मजबूत करना एवं विकासात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण विकास की समस्या बनी हुई है, तथा ग्रामीण विकास के लिए कृषकों को विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण योजनाओं से अज्ञात है तथा आज भी अधिकतम ग्रामीण जीविका हेतु परंपरागत आजीविका प्रणाली पर निर्भर है। इस व्याख्यात्मक शोध पेपर में हम यह तर्क देने की कोशिश करेंगे, कि किस तरह लघु उद्योग वर्तमान समय में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और योजनाओं को उचित क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार मुक्त आदि द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कृषि को परंपरागत कृषि प्रणाली के स्थान पर नवीन कृषि प्रणाली एवं लघु उद्योग पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं विकसित बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्द(Keywords): ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग, एक ज़िला एक उत्पाद,ग्रामीण जीविका, ग्रामीण आत्मनिर्भरता।

JEL: E24, R11, L10.

प्रस्तावना (introduction):-

भारत की अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यम के अधिक अवसर हैं अर्थात औद्योगिक व्यवसाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लघु उद्योग उत्पादकता, निर्यात और रोजगार सृजन के मामले में देश की अर्थव्यवस्था में अति महत्वपूर्ण योगदान देता है, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देता है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ (TWO) के अनुसार, छोटे पैमाने के उद्योग कुल औद्योगिक मूल्य वर्धित में 40% और स्कूल विनिर्माण निर्यात में लगभग 50% का योगदान रहता है जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए उचित प्रयास की जरूरत है। चंदौली जनपद की अर्थव्यवस्था लघु और कुटीर उद्योगों पर आधारित है, क्योंकि ग्रामीण जीवन ही चंदौली जनपद की आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की धुरी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएँ अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अगर हाल- फिलहाल की भारत की आर्थिक स्थिति को छोड़ दें, जो कि कोविड-19 से प्रभावित है, तो भारत की विकास दर पिछले कुछ समय से उच्च बनी हुई है जिसका कारण बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर बताई जा रही है। इन आर्थिक गतिविधियों में स्व-नियोजित महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। बचत, उपभोग-प्रवृत्ति के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था महिला केंद्रित मानी गई है। साथ ही हाल में रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि कर सरकार महिलाओं को इस क्षेत्र में भी मुख्य भूमिका निभाने का मौका देना चाह रही है। अतः महिलाओं की असीमित क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि इन्हें आर्थिक एवं सामरिक क्षेत्र के केंद्र में रखा जाए ताकि देश विकास के नए आयाम स्थापित कर सकें।

महिलाओं के उत्थान, विस्तार, विकास इत्यादि आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा, जिसके कारण हमें पहले चंदौली जनपद के भौगोलिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण की व्याख्यात्मक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। चंदौली जनपद जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का 48वां सबसे बड़ा जनपद है जिसमें पांच तहसील,ग्यारह कस्बे तथा नौ विकास प्रखंड है। चंदौली जनपद में जनसंख्या घनत्व 769 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात 918, जो राज्य के औसत 912 प्रति पुरुषों की तुलना में अधिक है।

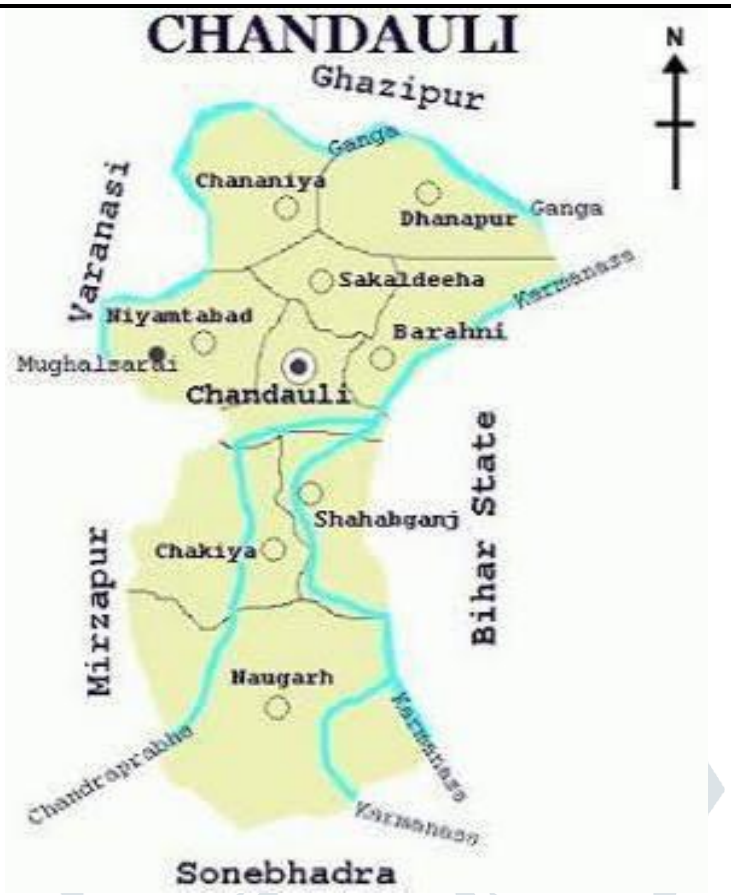

Fig.1.(Source:www.google.com/https://chandauliMap.in51255.)

जनपद चंदौली की साक्षरता दर 71.5% है, जनपद में कुल 1629 गांवों में से 204 निर्जन गांव हैं तथा चकिया तहसील में सबसे अधिक बसे हुए गांव 531 है ,जबकि चंदौली तहसील में सबसे कम 438 गांव है तथा जनपद में परिवारों की औसत आकार 6.6 व्यक्तियों का है।

जनसंख्या	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
व्यक्ति	1,71,020	2,42,553	19,52,756
पुरुष	8,90,630	1,27,275	10,17,905
महिला	8,19,573	1,15,278	9,34,851
अनुसूचित जाति	4,12,719	34,067	4,46,786
अनुसूचित जनजाति	37,688	4,037	41,725
साक्षरता	1,01,402	1,60,586	11,74,606
क्षेत्र फल वर्ग Km	2,487.28	5,372	2,541.00
जनसंख्या घनत्व	688	4,515	769
लिंगानुपात	920	906	918

Table1.(**Source**:census2011,chanduali,district,UttarPradesh, India)

- **लघु उद्योग क्या है?**

लघु उद्योग की अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई नहीं है, यह काफी प्राचीन काल की सदियों पुरानी परंपराओं और प्रणालियों को संबोधित करती हुई महापुरुषों का एक दृष्टिकोण है। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए लघु उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसकी समग्र आर्थिक विकास मैं इस उद्योग की अहम भूमिका होती है इसीलिए हर वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह दिवस लघु उद्योग के योगदान को दर्शाने बढ़ावा देने और बेरोजगारी को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से साल 2000 से हर वर्ष मनाया जाता है। लघु उद्योग वह उद्योग होता है, जो छोटे पैमाने पर किए जाते हैं और सामान्य रूप से मज़दूरों की सहायता से मुख्यता व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, वह उद्योग जिसमें 10 या 50 लोग मजदूरी के बदले काम करने को तैयार रहते हैं या करते हैं वह लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें निवेश यूपी सीमा सरकार द्वारा समय -समय पर बदलता रहता है। लघु उद्योग का मुख्य उद्देश्य है:-

1. रोजगार के अवसरों को सृजित करना है, ताकि बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके।
2. आर्थिक शक्तियों का समान वितरण करना है, अर्थात लघु उद्योगों से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है जिससे श्रम प्रधान तकनीक के कारण श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है।
3.

- **एक ज़िला एक उत्पाद योजना क्या है?**

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने तथा स्थानीय उत्पादों को एक अलग पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को 'उत्तर प्रदेश दिवस' के अवसर पर "एक जिला, एक उत्पाद योजना" को पांच वर्षों के लिए लाया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के उत्पाद विशेष के आधार पर छोटे मध्यम और परम्परागत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु योजना चलाई गई। केंद्र सरकार के सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों के विकास को बढ़ाने और रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना का शुरुआत किया गया। (one district one product -ODOP/https://www.ibef.org.in)

- **आर्थिक क्रिया से क्या तात्पर्य है ?**

स्वतंत्र अर्थात् स्वतः संचालित आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से स्वरोज़गार को सृजन कर अपनी आजीविका को सरल-सहज और बेहतर बनाने का प्रयास करता है।
उदाहरण के लिए : दुकानदार,स्व-नियोजित सिलाई-कढ़ाई श्रमिक, इत्यादि।

साहित्य समीक्षा (Literature Review):-

- **हिमांगिनी शर्मा(2017)** ने अपने शोध-"असंगठित श्रमिकों की समस्या का विश्लेषण" मैं बताया कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की भाँति सहायता तथा जरूरतों को पूर्ण किया जाए तो वे अधिक उत्पादन में भागीदारी कर सकती है।
- **सुनीता चौहान(2016)** ने अपने शोध प्रबंध शीर्षक-"भारत में महिला श्रमिक की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन" में बताया कि महिलाओं को घरेलू तथा व्यवसाय दोनों कार्य करने के बावजूद उनका आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता जबकि लगभग 80 से 90 प्रतिशत उत्पादन में महिलाओं का ही योगदान है। इन्होंने महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया है।
- **एम• कीर्तन(2014)** ने अपने शोध-"A study on problem faced by the women in the unorganised sector" में बताया किया असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं सामाजिक सुरक्षा, कम वेतन, शारीरिक शोषण इत्यादि जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **संतोष नंदलाल(2006)** ने अपने शोध प्रबंध-"Women worker in unorganised sector: A study of construction industries" में बताया कि निर्माण उद्योग में असंगठित रूप में कार्यरत महिलाएं जो प्रवासन करके दूसरे स्थान से आती है जिनका जीवन अत्यन्त कठिन तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दयनीय होती है।
- **सगुना वी(2001)** ने अपने शोध प्रबंध-"महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाओं की समीक्षा" उसने बताया कि महिलाओं के आर्थिक विकास में योगदान एवं समाज में उन्हें सम्मानित स्थान दिलाने हेतु हो रहे प्रयास एवं सुधारों पर ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।
- **एम• एच• और एम• पी• मैथ्यू(1981)** ने अपने शोध प्रबंध शीर्षक-"women unorganised and women investor" ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक संरचना में आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूमिका होती है।

शोध पत्र का उद्देश्य (Objective of Research Paper):-

1. एक ज़िला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण मे एक ज़िला एक उत्पाद योजना की भूमिका का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार स्थिति में होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण महिलाओं आर्थिक क्रियाओं का लघु उद्योग के विकास में भूमिका का अध्ययन करना।

शोध पत्र का क्षेत्र (Area of research paper):-

प्रस्तुत शोध पत्र चन्दौली के जरी जरदोजी जो साड़ीयो पर जरी अर्थात कड़ाई (Design) मे संलग्न महिला श्रमिकों पर केंद्रित है वस्तुतः शोध पत्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चन्दौली जनपद के समस्त महिला श्रमिकों को शामिल करना था, लेकिन इसका क्षेत्र अर्थात दायरा चंदौली जनपद के केवल नियामताबाद विकास प्रखंड तक ही सीमित है।

शोध प्रविधि (Research Methodology):-

प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन में शोध अभिकल्प की रूपरेखा को पूर्ण रूप देने के लिए वर्णनात्मक विश्लेषण (Descriptive Analysis) के माध्यम से व्याख्यात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तथा प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु प्रश्नावली और साक्षात्कार का तथा द्वितीय आंकड़ों के संकलन हेतु विभिन्न प्रकार के लेख, पुस्तकों, शोध प्रबन्ध, इंटरनेट, इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा ताकि वर्तमान स्थिति का सटीक जानकारी प्राप्त हो सकें।

प्रस्तुत शोध पत्र में शोध अभिकल्प (Research Design) के अंतर्गत स्तरिकृत प्रतिदर्श विधि(multistage Sampling Techniques) का प्रयोग कर चन्दौली जनपद के अन्तर्गत एक विकास प्रखंड का चयन उद्देशपूर्ण प्रतिदर्श(Convenience Sampling) के माध्यम से तीन पंचायतों का चयन भी उद्देशपूर्ण प्रतिदर्श(Convenience Sampling) का प्रयोग करके इन चयनित पंचायतों(सांतपोखरी,गोपालपुर और हमीदपुर) से 15-15 ग्रामीण महिला श्रमिकों से कुल 45 हिमककुद प्रतिदर्श(Snowball Sampling) के माध्यम से चयन किया जाएगा जो इस प्रकार है :-

Multistage Sampling Techniques

Stage	Sampling units	Sampling Nature
First Stage	District (जनपद)	उद्देशपूर्ण प्रतिदर्श
Second stage	विकास प्रखंडों	यादृच्छिक प्रतिदर्श
Third Stage	पंचायतों	उद्देशपूर्ण प्रतिदर्श
Fourth Stage	महिला श्रमिक	हिमककुद प्रतिदर्श

(Table 2. Sampling Techniques Methods)

शोध पत्र का अध्ययन(Study of Research Paper):-

उत्तर प्रदेश के "एक ज़िला एक उत्पाद योजना" को MSME , क्षेत्र के माध्यम से आत्मनिर्भर अर्थात् स्वलंबन बनाने हेतु सभी जनपदों में उत्पाद विशेष के सम्बन्ध मे छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों के

विकास को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय कारीगरों की खोई हुई पहचान को वापस दिलाने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है।

"एक ज़िला एक उत्पाद योजना" की परिकल्पना जापान सरकार द्वारा सन् 1979 को एक अंतर-संबंधी राज्य कल्याण सम्मेलन के दौरान हुई जिसे प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की अवधारणा से परिचित होकर तथा रोज़गार सृजन के उद्देश्य से राजकीय और जिला स्तर पर सन् 2018 को योजना की शुरूआत की गई।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान राज्य होने के कारण, लघु उद्योग पर आधारित है क्योंकि ग्रामीण जीवन ही प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की धुरी है। आज भी ग्रामीण लोग स्थानीय और परंपरागत विशिष्ट उत्पादों को विक्रय कर अपनी आजीविका चलाते है। इस शोध पत्र में यह जानना बहुत रोचक होगा की क्या वास्तव मे एक ज़िला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिला श्रमिकों की, जीवन-निर्वाह, स्वलंबन, आर्थिक स्थिति इत्यादि मे सुधार हुआ है।

- **भारत में लघु उद्योग का महत्व निम्नलिखित है:-**

रोजगार में वृद्धि:-भारत में जनाधिक्य के कारण बेरोजगारी की समस्या व्यापक रूप से पाई जाती है , लघु उद्योग श्रम प्रधान होने के कारण इन्हें उद्योगों द्वारा कम पूंजी के विनियोग से भी रोजगार में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

1. **कृषि जनसंख्या के भार में कमी:-**भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की लगभग 58.2% कार्यशील जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 32,00,000 व्यक्ति खेती पर आश्रित होने के लिए अग्रसर होते हैं परन्तु लघु उद्योग से इस समस्या का समाधान निहित है।
2. **उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता:-**लघु उद्योग से देश में सभी उद्योगों को विकेंद्रीयकरण में सहायता प्राप्त होती है।
3. **परंपरागत एवं कलात्मक वस्तुओं का संरक्षण:-**लघु उद्योग हमारी परंपराओं एवं कलात्मक वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करते है। जैसे:-बनारसी साड़ियां, हाथीदांत का कार्य, प्राचीन पत्थरों के आभूषण, इत्यादि में भारत प्राचीन समय से ही विदेशी आय अर्जित कर रहा है ।
4. **कम तकनीक ज्ञान की आवश्यकता:-**लघु उद्योगों की स्थापना न्यूनतम पूंजी के साथ – ही – साथ कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अंततः लघु उद्योगों की स्थापना से आर्थिक एवं सामाजिक निर्भरता में वृद्धि होती है।
5. **निर्यात में सहायक:-**बीते कुछ वर्षों में भारत में लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हुई है।

- भारत में 6.3 करोड़ से अधिक एमएसएमई है,

- जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख के लिए सहायक रूप में काम करने की बृहद क्षमता है। निर्यात के संदर्भ में, इस क्षेत्र में शामिल मधु जैसे – कपड़ा, चमड़े, ऑटोमोटिव, रत्न और आभूषण आदि में 45% के समग्र योगदान के साथ उच्च संभावनाएँ निहित है यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 जून को हम एसएमई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया यहाँ 2017 के बाद से हर वर्ष यह दिवस मनाया जा रहा है। (Dr.Ankita Gupta,MGKVP,Varanasi-"Indian Economy Forthcoming")
- "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(Small Industries Development Bank of India-SIDBI)एसटीएफ स्थापना 2 अप्रैल 1990 को दी गई थी इसका मुख्यालय- लखनऊ(उत्तर प्रदेश) में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के साथ-साथ समान गतिविधियों से जुड़ें संस्थाओं के कार्यों ने समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना है। (https://www.google.nic.org.)

उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में :-

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अधिकांश कृषि पर आधारित है,जो ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परन्तु उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ ही साथ लघु, मध्यम और कुटीर उद्यम की अधिक अवसर है, जो ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है । विश्व व्यापार संगठन(WTO) के अनुसार- छोटे पैमाने के उद्योग का कुल ओद्योगिक मूल्य वर्धित मे 40 प्रतिशत और विनिर्माण निर्यात में 50 प्रतिशत का योगदान रहा है जिसमें निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उचित प्रयास की आवश्यकता है

ग्रामीण जीवन ही चन्दौली जनपद की प्रधान विशेषता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की लघु उद्योग के विकास मे अति महत्वपूर्ण भूमिका है, परन्तु महिला श्रमिकों को चिन्हित करना और उनको योजना का लाभ दिलाना सबसे बड़ी चुनौती है।

वर्तमान वर्ष 2022 में लगभग 25,00,000 बेरोज़गारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य है। इस योजना के तहत चंदौली जनपद मैं –" जारी-जरीदोजी "जो साड़ियों पर जरी का अधिकांश काम चंदौली जनपद के नियामताबाद विकास प्रखंड के गांव गोपाल पुर, दुलहीपुर , सतपोखरी , सिकंदरपुर और केतससर के कारीगरों द्वारा किया जाता है।

- **उत्तर प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की प्रमुख समस्या :-**
  1. **काम आय:-**असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की कम आय होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होती है।
  2. **अस्थाई रोज़गार:-** असंगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार अर्थात अस्थायी रोजगार की गारंटी ना होने के कारण ग्रामीण महिला मजदूर निम्न मजदूरी दर और असुरक्षित कार्यस्थल पर कार्य करने को विवश है।

3. **श्रम कानूनों का लाभ नहीं:-** श्रम कानून तथा खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ नहीं परन्तु इस कानून के अनुसार महिलाओं को उचित पोषण के लिए छह हजार रुपए तक की सरकारी सहायता देने का नियम है, कामगार महिलाएं इस सुविधा से वंचित हैं।
4. **आर्थिक और सामाजिक जीवन का अभाव:-** असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के आर्थिक ओम सामाजिक जीवन का अभाव देखने को मिलता है क्योंकि श्रम कानून का अनुपालन न के बराबर होता है।
5. **मजदूरी मे भेदभाव:-** ग्रामीण पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों की मजदूरी दर में भेदभाव होता है क्योंकि महिला और पुरुष श्रमिकों की उत्पादकता स्तर भिन्न- भिन्न होती है।
6. **मातृत्व अवकाश की सुविधा का अभाव:-** असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों के मातृत्व अवकाश की सुविधा का अभाव होता है,जिससे उनकी सामाजिक जीवन प्रभावित होती है।
7. **यौन उत्पीड़न:-** असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण महिला श्रमिकों को लगातार बाहरी तत्वों के माध्यम से यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

शोध पत्र का महत्त्व (Important of Research Paper) :-

लघु और कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र मे कार्यरत महिलाओं की आर्थिक एवम् सामाजिक स्थिति के उत्थान के लिए सरकार द्वारा निरंतर उल्लेखनीय प्रयास के बावजूद निम्न मजदूरी दर पर कार्य करने को विवश है,तथा आजीविका के लिए पारंपरिक संघर्ष अब भी जारी है। परन्तु इस शोध पत्र अध्ययन का महत्त्व यह है कि ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक आर्थिक स्थिति को 'एक ज़िला एक उत्पाद योजना' के अंतर्गत उनकी भूमिका को बताना है।

आकड़ो का विश्लेषण (Analysis of Data):-

एकत्रित अकड़ो के विश्लेषण एवं उसकी व्याख्या से यह अनुमान लगाया जाएगा कि एक ज़िला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में कितना और कहा तक कामयाब हुई है। आकड़ो के विश्लेषण के लिए प्रतिशतता एवम् सारणी का प्रयोग कर अपने शोध पत्र के उद्देश्यों के अनुसार तीन भागों मे विभक्त किया गया है जो निम्नलिखित है :-

1. उत्तरदात्री की जाति और रोज़गार की स्थिति।
2. उत्तरदात्री की आय सृजन का स्तर।
3. उत्तरदात्री की मजदूरी दर की स्थिति।

विकास प्रखंड	जाति	रोज़गार संलग्न	महिला श्रमिकों की संख्या	रोज़गार की प्रकृति
1. नियामताबाद	सामान्य वर्ग	जरी-जरदोजी	5	अनियमित
	अन्य पिछड़ा वर्ग	जरी-जरदोजी	13	अनियमित
	अनुसूचित जनजाति	जरी-जरदोजी	18	अनियमित
	अनुसूचित जाति	जरी-जरदोजी	9	अनियमित
कुल			**45**	

Table 1.उत्तरदात्री की जाति और रोज़गार की स्थिति

विकास प्रखंड	जाति	रोज़गार संलग्न	आय का वार्षिक स्तर (हज़ार मे)
नियामताबाद	सामान्य वर्ग	जरी-जरदोजी	84,000
	अन्य पिछड़ा वर्ग	जरी-जरदोजी	81,600
	अनुसूचित जनजाति	जरी-जरदोजी	74,400
	अनुसूचित जाति	जरी-जरदोजी	78,000
कुल			**3,18,000**

Table 2.उत्तरदात्री की आय सृजन का स्तर

विकास प्रखंड	जाति	उम्र	महिला श्रमिकों की संख्या	रोज़गार संलग्न	मजदूरी (मासिक दर पर)
1.नियामताबाद	सामान्य वर्ग	21-25	5	जरी-जरदोजी	7,000
	अन्य पिछड़ा वर्ग	25-30	13	जरी-जरदोजी	6,800
	अनुसूचित जनजाति	30-35	18	जरी-जरदोजी	6,200
	अनुसूचित जाति	35 से ऊपर	9	जरी-जरदोजी	6,500
कुल			**45**		**26,500**

Table 3.उत्तरदात्री की मजदूरी दर की स्थिति

Source: शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया आंकड़ों का नमूना

महत्वपूर्ण निष्कर्ष (Conclusion & Finding):-

उक्त आंकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, क्योंकि अनियमित रोज़गार की प्रवृत्ति तथा मजदूरी दर निम्न तथा स्थिर वार्षिक आय होने के साथ-साथ जोखिमपूर्ण कार्यस्थल पर काम करने पर विवश है जबकि महंगाई दर निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आज भी उनकी आर्थिक सशक्तिकरण एवम् सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य जैसा प्रतीत हो रहा है और तकनीकी कौशल ना होने के कारण एक ज़िला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रुप से संकुचित होती जा रही है।

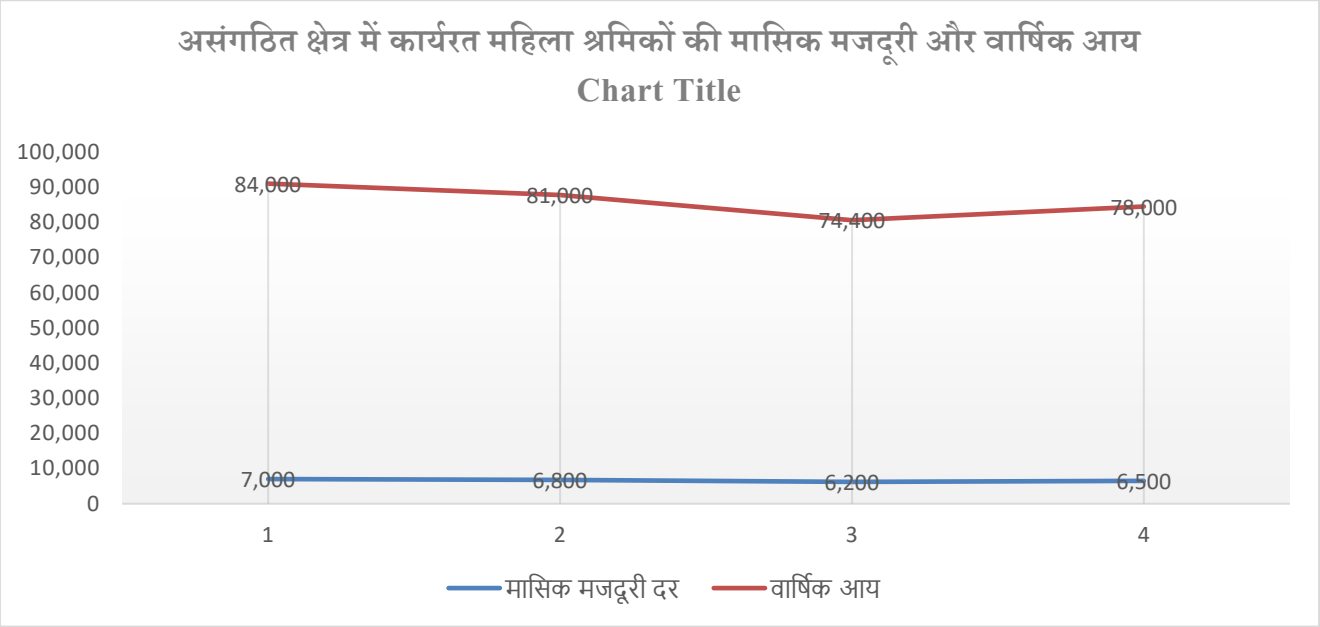

सुझाव (Suggestions):-

1. महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न वित्तीय समावेशन जागरूकता अभियान एवम् योजनाओं का क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
2. 'उद्यम सखी पोर्टल' से अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को जोड़ना तथा वित्तपोषण कर स्वलंबन होने को प्रोत्साहित करना।
3. बोनस अधिनियम 1965 के तहत कुछ अतिरिक्त वित्तीय भुगतान करना चाहिए जिससे महिलाएं आर्थिक सशक्त बन सकें।
4. एक ज़िला एक उत्पाद योजना मे कार्यरत ग्रामीण महिला श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कौशल विकास योजनाओं से जोड़ना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची(Reference):-

- शुक्ला,अर्चना(2015)Aijarvol.issue2,2015,ISSN,24555967"Issues,of challenge of women workers in unorganised sector in India".
- डा० लक्ष्मी बाई (2018)-" असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की समस्या".
- सुगना वी०(2001)-"महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाओं की समीक्षा"

- Shivangi,Singh,(2018)ISSN(Print),2249-0302,ISSN(online),2231-2528, volume5, Issue 1.janurary 2018.
- Krishna M.D ISSN,2321-4171"Supporting services for working women in India in unorganised sector: A critical Analysis.
- उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी (District statistical Magazine 2018-19).
- जनगणना 2011, भारत सरकार (https://censusIndia.gov.in/2011)
- https://www.chandauli.nic.in/:28sep.2022
- https://www.wikipedia.org.in/:22oct,2022.
- https://www.google.org.in/:18oct,2022.
- https://wwww.ijcmss.in .
- https://www.updes.up.nic.in/:28Nov.2022.